

प्रेषक,

एम०एच०खान

सचिव

उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड ।

पेयजल अनुभाग- 2

देहरादून: दिनांक: 4 मई, 2008

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रति विधान सभा 10 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट के दृष्टिगत उत्तराखण्ड जल संस्थान के पत्र संख्या 425/वि०अनु०/02/अनुदान/2008-09 दिनांक 01.05.08 द्वारा राज्य के पर्वतीय जनपदों की 45 विधान सभा क्षेत्रों में 10-10 हैण्डपम्प प्रति विधान सभा अर्थात् कुल 450 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु रु० 1089.00 लाख तथा उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पत्र संख्या 1332/धनावंटन प्रस्ताव/दिनांक 22.04.08 द्वारा राज्य के मैदानी जनपदों (देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर) की कुल 25 विधान सभा क्षेत्रों में 11 हैण्डपम्प प्रति विधान सभा की दर से रु० 250.14 लाख की माँग की गई है। उपरोक्त प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त शासन स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा मैदानी जनपदों (देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर) में प्रति विधान सभा क्षेत्र 10 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु रु० 227.40 लाख तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा राज्य के शेष पर्वतीय जनपदों में कुल 450 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु रु० 1089.00 लाख अर्थात् कुल रु० 1316.40 लाख (रु० तेरह करोड़ सोलह लाख चालीस हजार मात्र) की कार्ययोजना पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्न विवरणानुसार जनपदवार रु० 157.03 लाख (रु० एक करोड़ सत्तावन लाख तीन हजार मात्र) उत्तराखण्ड पेयजल निगम के पक्ष में तथा रु० 435.51 लाख (रु० चार करोड़ पैंतीस लाख इक्कावन हजार मात्र) उत्तराखण्ड जल संस्थान के पक्ष में अर्थात् कुल रु० 592.54 लाख (रु० पाँच करोड़ बयानबे लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु निम्न विवरणानुसार जनपदवार जिला योजना के अधीन हैण्डपम्प अधिष्ठापन मद के अन्तर्गत आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि रु० लाख में)

क्र० सं०	जनपद	स्वीकृत हैण्डपम्पों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	स्वीकृत की जा रही धनराशि		
				जल निगम	जल संस्थान	योग
1	पौड़ी	72	193.60	—	77.72	77.72
2	चमोली	40	96.80	—	38.68	38.68
3	रूद्रप्रयाग	20	48.40	—	19.34	19.34
4	टिहरी	60	145.20	—	58.02	58.02
5	उत्तरकाशी	30	72.60	—	29.01	29.01
6	नैनीताल	50	121.00	—	48.35	48.35
7	अल्मोड़ा	70	169.40	—	67.69	67.69
8	पिथौरागढ़	50	121.00	—	48.35	48.35
9	चम्पावत	20	48.40	—	19.34	19.34
10	बागेश्वर	30	72.60	—	29.01	29.01
11	देहरादून	90	141.30	87.03	—	87.03
12	हरिद्वार	90	65.10	49.00	—	49.00
13	उधमसिंह नगर	70	21.00	21.00	—	21.00
	योग:-	692	1316.40	157.03	435.51	592.54

- (2) उत्तराखण्ड पेयजल निगम को आवंटित धनराशि का आहरण सम्बन्धित जनपदों में उत्तराखण्ड पेयजल निगम के नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा उस जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित युक्त बिल तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान को आवंटित धनराशि का आहरण सम्बन्धित जनपदों के उत्तराखण्ड जल संस्थान के नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर तथा उस जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल सम्बन्धित जिलों के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकता के अनुसार आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।
- (3) स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन शासनादेश संख्या 1016/उन्तीस /05-2-पे0/2005, दिनांक 15.05.2005 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद स्तर पर मा0 सासद, मा0 विधायकगण, सम्बन्धित विभाग के अधिशारी अभियन्ता, जिला पंचायत के प्रतिनिधि एवं मुख्य विकास अधिकारी को सम्मिलित कर समिति गठित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर मा0 विधायकगणों की संस्तुति उपरान्त निर्धारित कर ली जाय। धनराशि का व्यय अनुमोदित स्थलों/कार्यों पर ही किया जायेगा। ऐसे कार्यों पर धनराशि कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है अथवा जो विवाद ग्रस्त है।
- (4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों एवं विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (5) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय। गुणवत्ता हेतु पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता का होगा।
- (6) अवमुक्त की जा रही धनराशि के 80 प्रतिशत या उससे अधिक उपभोग सुनिश्चित होने पर शासन को प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही शेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 30.06.08 तक पूर्ण उपयोग कर उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं धनराशि के उपयोग का विवरण मासिक रूप से भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे हैण्डपम्प ऐसे स्थानों पर कदापि नहीं लगाये जायेंगे जहाँ पर पूर्व में हैण्डपम्प अधिष्ठापित हों।
- (9) उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुदान सं0-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति- आयोजनागत-101-शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम-05-नगरीय पेयजल-91-हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन (जिला योजना)-20- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे" डाला जायेगा।
- (10) यह आदेश नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0रा0/2008, दिनांक 24.03.08 में दी गई व्यवस्था के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
सचिव

संख्या-905/उन्नीस(2)/07-2(27पे0)/2007,तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
- 2-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
- 3-मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल ।
- 4-समस्त कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड ।
- 5-प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून ।
- 6-मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून ।
- 7-महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पौड़ी/नैनीताल ।
- 8-मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम गढ़वाल/कुमायूँ
- 9-वित्त अनुभाग-2/वित्त,बजट सेल/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
- 10-स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- 11-निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
- 12- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून ।

आज्ञा से

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव